(ख) सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिए सतत प्रयास करने और आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सतत अभियान चलाने के अलावा, जम्मू और कश्मीर सरकार ने सभी संबंधियों को सलाह दी है कि काम करने के लिए राज्य के बाहर से आने वाले ऐसे व्यक्तियों को भीतरी क्षेत्रों, जो इस प्रकार के आसान लक्ष्यों के प्रति लक्षित आतंकवादी गतिविधियों के लिए संवेदनशील हो सकते हैं, में जाने से बचना चाहिए। मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों को भी सलाह दी गयी है कि वे अपने ठहरने के स्थान इत्यादि के बारे में ब्यौरे नजदीक के पुलिस स्टेशन को दें, ताकि आवश्यक सतर्कता और सुरक्षा उपाय किए जा सके।

(ग) कुपवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट ने प्रत्येक मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को 1 लाख रु० की दर से अनुग्रहपूर्वक राहत स्वीकृत की है, जिसे बलिया के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।

Closing Down of Power Plants

1821. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of Power Plants which had to close down during the last year due to non-supply of required quantity of coal; and

(b) the corrective steps being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) No power station was closed down during the last year on account of non-supply of required quantity of coal. However, a few power stations had to reduce generation by shutting of units due to less supply of coal. The coal availability in the Country is being augmented through higher production and greater coordination in its movement by Railways etc.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर व्यय

1822. **श्री इकबाल सिंह:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान और प्रोद्योगिकी हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया है;

(ख) अब तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अनुसंधान और विकास पर व्यय, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.83 प्रतिशत है, उसे बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या आवश्यक तथा ठोस कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के०अलघ): (क) आठवीं योजना परिव्यय के कुल 4119.00 करोड़ रुपये की तुलना में, विज्ञान और प्रोद्योगिकी एजेंसियों/विभागों के लिए वास्तविक योजना परिव्यय 6266.00 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्ष 1992-96 के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:—

रुपये करोड़ में

1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	481.04
2.	महासागर विकास विभाग	154.50
3.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	780.18
4.	वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग	600.93
5.	अंतरिक्ष विभाग	2265.71
6.	जैव प्रोद्योगिकी विभाग	313.78
7.	फौरेंसिक सायंस और पुलिस वायर लैस	5.95

(ग) सरकार इस विचार से अवगत है कि अनुसंधान तथा विकास पर खर्च को कुल राष्ट्रीय उत्पाद के 2 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।